SHRI PRANAB MUKHERJEE: Unless the process is complete, it cannot be sent to the Government. The Government can bring a Bill after the process has been completed by that Committee.

SHRI NILOTPAL BASU: I was very clear that the Bill is under the consideration of the Standing Committee. That is why there is more urgency to have proper coordination between the Standing Committee and the Government so that the Bill is passed in this Session itself

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Standing Committee should send the report.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Let the Committe consider the Bill. If the Ministry delays the report after it has been sent to it by the Standing Committee, we can pass on the buck to the Ministry. (Interruptions) Mr. Nilotpal basu, please don't dictate how quickly or how fast the Standing Committee should deal with it. Then it would be another dereliction of duty on our part. Please don't do that. It has never been done. The Department-related Standing Committee takes its own time to complete the process, and I think, Madam, you should stop him from doing that. There should be no reflection on the functioning of the Department-related Standing Committee. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Department-related Standing Committee is an extension of the Parliament itself. The Committee is seized of the mater. A Bill of that magnitude, which covers even the Prime Minister's office and every other functionary, has to be examined and the Committee-whoever be its Members and Chairman is looking into all the aspects of it. Now, until and unless the Committee has laid its report on the Table of both the Houses, I don't think we can have the Bill, and it was rightly pointed out by the former Minister, Mr. Pranab Mukherjee, that we cannot direct the Committee which we have appointed because it is a part of us. We can request the Committee because now the matter is in the hands of the Committee. We can request the Committee to expedite the matter, but we cannot put the blame for delay on the Parliamentary Affairs Ministry.

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, I am not criticising. I am just drawing the attention of the House for expression of greater urgency because o the prevailing circumstances. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am quite sure that there are Members from this House also in the Committee and there are Members from all political parties. You can, at your own level, talk to them and see that they expedite the matter and take this into account.

---

## RE. DEMONSTRATION BY POOR PEASANTS OF KERALA HILL REGIONS IN DELHI

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (ANDHRA PRADESH): Thank you, Madam. I rise to bring to the notice of this august House an agitation which is going on now outside the precincts of the Parliament House and some of our Members also had gone there to express their solidarity with the agitators. As far as my information goes, a number of agitators, along with our own Members, have also been arrested. The problem is about one lakh peasants in Kerala, specially in the eastern hill areas of Kerala, who occupied some lands belonging to the Forests Department some decades ago. They reclamated the land and then began cultivating it and started living on those small pieces of land. Now the problem has arisen because the Forests Department is asking them to vacate these lands. All of a sudden, Madam, after spending decades of their lives on these lands, after spending a lot of money and energy in reclaiming these lands, they cannot go out and make a living outside. And suddenly, they cannot shift their occupation at this stage. Therefore, the Revenue Minsiters' conference that was held last year, had also recommended that these lands should be regularised and the required amendment to the Indian Forests Act be made. If that Act is amended in a suitable manner, lakhs of these poor farmers who have been living on these lands for the last so many years, can have their living. That is the urgency of the matter. Hundreds of people representing one lakh peasants have come to this city and they are courting arrest.

I request the Government to look into the matter urgently to save the lives of these people. Thank you, Madam.

DR. (SHRIMATI) BHARATI RAY (WEST BENGAL): Madam, I also associate myself with his Special Mention. May I take a minute, Madam?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. You have associated yourself with it, and your association is appreciated, by everybody, I am sure, because this is how I can finish the work!

---

## RE: AK-47 ASSAULT RIFLES LYING UNUSED FOR WANT OF AMMUNITION

**श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश):** मैडम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

**उपसभापति:** तालियां क्यो बजी? मेडन है?

**श्री नरेन्द्र मोहन:** ये जो राइफलें एक लाख खरीदी गयीं 1993 में उनके लिए एम्युनिशन अभी तक नहीं आ रहा है। एक अजीब बात है कि जहां एक ओर हमारा प्रतिरक्षा मंत्रालय सफलता पा रहा है रूस से प्रोद्योगिकी लेने में और विमान लेने में, बधाई का पात्र बन जाता है वहीं उस मंत्रालय में एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो गयी है कि जिसके कारण से बहुत से हथियार जो खरीदे जा चुके हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता है। केवल यह एके॰47 की बात ही नहीं है बल्कि अगर इसी वर्ष की आडिट रिपोर्ट को देखा जाए तो बहुत से ऐसे मामले सामने आएंगे। मैं यह दरखास्त करना चाहता हूं कि यह मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि एके॰47 राइफलें जो खरीदी गयी है वे इस इरादे से खरीदी गयी थीं कि उनसे हम आतंकवादियों का सामना करेंगे। हमारी बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास, हमारी आर्मी के पास अच्छे किस्म के हथियार नहीं थे इसी लिए एके॰ 47 राइफलें खरादी गयीं। राइफलें तो आ गयी हैं लेकिन उनकी गोलियां नहीं आईं। राइफलें हमने रोमानियां से खरीदीं, पहले बल्गारिया से खरीदने वाले थे लेकिन खरीदी रोमानिया से और हमने गोलियों के लिए करार किया उत्तरी कोरिया के साथ। उत्तरी कोरिया की एक कम्पनी ने कह दिया कि उनके पास अभी हालत ऐसे नहीं हैं कि वे हमें गोलियां दे सकें। परिणाम यह हुआ है कि हथियार आ गए और वे हथियार न तो बार्डर सिक्योरिटी के पास जा सके न तो सेना के पास जा सके।

**श्री हेच॰ हनुमनतप्पा (कर्नाटक):** मैडम, यह तो डिफेंस की इन्फारमेशन है कि हमारे पास हथियार है, बारूद नहीं है। यह इन्फारमैशन पार्लियामेंट से बाहर क्यों जाए।

**उपसभापति:** अखबार में खबर आयी है आरै वे अखबारवाले हैं।

**श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश):** इसी वजह से कि वह कमी पूरी हो जाए देश में—मैं समझता हूं कि यह उचित है। हनुमनतप्पा जी बड़े अनुभवी है और ऐसे मामले उठाते रहे हैं। अब एक सदस्य अपने पहले भाषण में ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो कि देश की सुरक्षा से संबंधित है।

**उपसभापति:** मेडन स्पीच में वे भी एके॰47 चला रहे हैं बगैर गोलियों के तो चलाने दीजिए।

**श्री हेच॰ हनुमनतप्पा:** आई एम सारी।

**उपसभापति:** उसमें तो गोलियां भी नहीं है। उनकी तो एके॰47 एकदम खाली है।

**श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी:** ऐसा है कि इसमें मेडन वैशफुलनेस तो नहीं है। उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया है।

**उपसभापति:** मैं तो खुश होउंगी कि सब ही मेडन स्पीच करें हाउस में ताकि कोई डिस्टरबैंस नहीं हो।

**श्री नरेन्द्र मोहन:** महोदया, आज स्थिति क्या है? अभी इन्सरजेंसी जिस तरह उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ रही है, विशेष रूप से आसाम में बढ़ रही है, बोडोलैंड में बढ़ रही है और नागालैंड में बढ़ रही है और हम उसका मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वहां जो बार्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनके पास आधुनिकतम हथियार नहीं है। यह बात जो कही गयी है यह वहां आसाम के अधिकारियों ने और आसाम के मुख्य मंत्री तक के द्वारा कही गयी है। अब उनको हथियार कैसे पहुंचाए जाएं यह एक बड़ा अहम मसला है। आप काश्मीर की बात ले लीजिए। काश्मीर में भी इन्सरजेंसी पूरी तरह से जागरूक है। वहां के भी पुलिस और बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास हथियार नहीं हैं सेना के पास जरूर है लेकिन बार्डर सिक्योरटी फोर्स के पास उस अच्छे किस्म के हथियार नहीं है जैसी अच्छी किस्म के हथियार उन आतंकवादियों के पास हैं जो वहां जाकर गड़बड़ियां पैदा करते है। ये ऐसे हालात हैं जिनके ऊपर हमें नजर डालनी होगी। सबसे अफसोस की बात यह है कि भारत में जो आयुध कारखाने हैं वे अच्छी किस्म की असाल्ट राइफलें नहीं बना पाते हैं। ऐसा क्यों है? भारत में जो भी हथियार के कारखाने हैं उनके यहां जो हथियार बनते हैं उनकी किस्म बहुत घटिया हो गयी है। यह बात मेरी नहीं है यह आडिट रिपोर्ट्स की बात है।

**1.00 P.M.**

जो इसी वर्ष की आडिट रिपोर्ट में है। यह चिंता की बात है। जैसा कि आडिट रिपोर्ट में कहा गया है। मैं उस हिस्से को पढ़ना चाहूंगा: